

अनुदान संख्या:10-लेखाशीर्षक 2055-पुलिस का आउटकम बजट

आउटकम बजट:-2017-18

(धनराशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	आउट-ले 2017-18		परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट पुट	समय-सीमा	परिकल्पित (प्रोजेक्ट) आउट कम	समय-सीमा
			राजस्व	पूँजीगत				
राज्य सैक्टर								
1	निदेशन और प्रशासन	प्रदेश में पुलिस विभाग पर कानून व्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण बनाये जाने हेतु।		-	पुलिस मुख्यालय के 395 अधिकारी/कर्मचारी एवं दो परिक्षेत्रीय कार्यालय गढवाल व कुमायूँ में नियुक्त 19 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर नियन्त्रण हेतु सीधे जनपदों एवं परिक्षेत्रीय कार्यालयों का पर्यवेक्षण तथा राज्य में अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने हेतु मानव संसाधन का सृजन।	2017-18
2	अग्नि से संरक्षण एवं नियंत्रण अधिष्ठान	आपात स्थिति में अग्निकांड एवं अन्य स्थितियों से निपटने हेतु सदैव तत्पर		-	अग्निशमन एवं आपात सेवा के 1050 अन्तर्गत नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	उत्तराखण्ड राज्य में अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा दैवीय आपदा के समय तत्काल घटनास्थलों पर पहुंच कर बचाव एवं राहत कार्य सम्पादित।	2017-18
3	राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद्	उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के कल्याण हेतु गठित		-	राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण हेतु गठित परिषद् के अन्तर्गत अधिष्ठान व्यय	2017-18	राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन।	2017-18
4	राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान	राज्य स्तर पर पुलिस अधि०/कर्मचारियों की शिकायतों का निस्तारण		-	राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान में नियुक्त 12 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण में पुलिस के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कर जनसाधारण में पुलिस के प्रति विश्वास बनाना।	2017-18
5	राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ	राज्य में महिला से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण।		-	प्रदेश में राज्य महिला सहायता प्रकोष्ठ के अन्तर्गत प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	प्रदेश में मुख्यालय स्तर एवं जनपदों पर स्थापित महिला सहायता प्रकोष्ठ के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण कर सहायता प्रदान करना।	2017-18

6	अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई	अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु	-	अवैध खनन निरोधक सतर्कता इकाई में नियुक्त 11 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	प्रदेश में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही।	2017-18
7	राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष	राज्य निर्माण आन्दोलनकारियों के कल्याण कोष का गठन	-	राज्य आन्दोलनकारी कल्याण कोष हेतु प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	राज्य आन्दोलनकारियों के कल्याणार्थ गठित कोष से राज्य आन्दोलनकारियों को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराना।	2017-18
8	यातायात व्यवस्था का सुधार	राज्य में बेहतर यातायात व्यवस्था बनाये रखना	-	यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु उपकरणों एवं आवश्यक संसाधनों के क्रय हेतु प्रासंगिक व्यय।	2017-18	जनपदों के अन्तर्गत यातायात व्यवस्था में आवश्यक सुधार एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू व सुगम बनाया जाना।	2017-18
9	शिक्षा और प्रशिक्षण	राज्य में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान कर कार्यक्षमता में सुधार	-	प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत नियुक्त 153 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	पुलिस विभाग में नियुक्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित कार्मिकों को समय-समय पर राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर विभिन्न प्रशिक्षण कराकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि करना- प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लिये गये प्रशिक्षण का लाभ अपराध नियन्त्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने में हो रहा है।	2017-18
10	अपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	राज्य में गोपनीय सूचनाओं को संकलित कर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखना	-	अभिसूचना इकाई, सुरक्षा व्यवस्था, सी0आई0डी एवं भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण हेतु नियुक्त 780 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	उत्तराखण्ड राज्य की अधिकांश सीमा अन्तर्राष्ट्रीय बार्डर चीन, नेपाल, तिब्बत से लगी है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आतंकवादी घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुये राज्य एवं देश की जनता की सुरक्षा के मध्यनजर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अभिसूचना तंत्र को सुदृढ करते हुये अभिसूचना संकलन किया जाना।	2017-18
11	विशेष पुलिस	कानून व्यवस्था बनाये रखने में पुलिस को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।	-	03 वाहिनी पीएसी तथा 02 इण्डिया रिजर्व वाहिनी में नियुक्त 5667 अधिकारियों/कर्मचारियों तथा एस0टी0एफ0 में नियुक्त 38 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	राज्य में वर्तमान में 03 वाहिनी पीएसी तथा 02 इण्डिया रिजर्व वाहिनी स्थापित है, जिनकी राज्य एवं राज्य से बाहर कानून व्यवस्था ड्यूटी हेतु नियुक्त की जाती हैं तथा एस0टी0एफ0 द्वारा राज्य में अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का अनावरण के साथ ही साथ संगठित अपराधिक गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश हेतु।	2017-18
12	निर्वाचन	राज्य में निर्विवाद	-	विभिन्न निर्वाचन के दौरान प्रासंगिक	2017-18	लोकसभा/विधानसभा निर्वाचनों के दौरान शांति एवं	2017-18

		निर्वाचन व्यवस्था सम्पन्न कराना।			मद में व्यय		कानून व्यवस्था बनाये रखना।	
13	स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स	आपदा, राहत एवं बचाव कार्य में तत्काल राहत कार्य करना।		-	स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स में नियुक्त 461 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	एस0डी0आर0एफ0 द्वारा दैवीय आपदा के समय तत्काल घटनास्थलों पर पहुंच कर बचाव एवं राहत कार्यों का सम्पादन।	2017-18
14	जिला पुलिस	राज्य में अपराध एवं कानून व्यवस्था बनाये रखना।		-	जिला पुलिस एवं जिला पुलिस रेडियो अधिष्ठान, परिवहन अधिष्ठान, घुड़सवार पुलिस में नियुक्त 15800 अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय। रेडियो अधिष्ठान हेतु 400-हैण्ड हैल्ड सेट, 250-स्टेटिक सेट तथा 20-रिपीटर सहवर्ती उपकर्मिकाओं के क्रय तथा सी0सी0टी0वी0 व डायल-100 की ए0एम0सी0, हैण्ड-हैल्ड/स्टेटिक सेटों की बैटरी क्रय इत्यादि सहित विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के अनुरक्षण/लघु निर्माण में व्यय।	2017-18	जिला पुलिस के अन्तर्गत स्थापित विभिन्न इकाईयों जिसमें नागरिक पुलिस, सशस्त्र पुलिस द्वारा राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुये अपराध नियन्त्रण किया जाना तथा मानव संसाधनों का सृजन, जनपद के रेडियो अधिष्ठान द्वारा पुलिस विभाग की संचार व्यवस्था को सुचारु ढंग से व्यवस्थित किया जाना। तथा जनपद में पुलिस बल के तत्काल मूवमेंट हेतु मोटर परिवहन अधिष्ठान द्वारा विभाग के वाहनों का सुचारु रूप से रख रखाव का कार्य किया जाना। विभिन्न आन्दोलनों के दौरान उग्र भीड़ पर नियन्त्रण हेतु घुड़सवार पुलिस इकाई द्वारा विभाग के अश्वों के द्वारा आक्रोशित भीड़ को नियन्त्रण का कार्य किया जाना।	2017-18
15	ग्राम पुलिस	राज्य में नियुक्त ग्राम चौकीदारों द्वारा ग्राम स्तर की सूचनाओं को पुलिस से साझा करना तथा अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।		-	जनपदों में नियुक्त 3334 ग्राम चौकीदारों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	ग्राम पुलिस में नियुक्त स्वयं सेवकों द्वारा अपने ग्राम की विभिन्न गतिविधियों की सूचना पुलिस विभाग को प्रदान किये जाने का कार्य किया जाना तथा पुलिस से सामंजस्य बनाकर पुलिस को अपना सहयोग दिया जाना।	2017-18
16	रेलवे पुलिस	राज्य की सीमा में सुरक्षित रेल यातायात व्यवस्था बनाये रखना।		-	रेलवे पुलिस अधिष्ठान के अन्तर्गत नियुक्त 155 अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	राज्य के जनपद हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल में रेलवे पुलिस अवस्थित है। रेलवे पुलिस द्वारा राज्य के अन्दर रेलयात्रा को भयमुक्त एवं सुरक्षित बनाये रखने का कार्य।	2017-18

17	पुलिस कार्मिकों का कल्याण	पुलिस विभाग में नियुक्त कार्मिकों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का संचालन।	-	पुलिस कार्मिकों के कल्याण के अन्तर्गत पुलिस विभाग के विभिन्न जनपदों एवं वाहिनियों में स्थापित पुलिस चिकित्सालय में नियुक्त 45 अधिकारियों/कर्मचारियों (चिकित्सकीय स्टाफ) के वेतन एवं चिकित्सालय व कार्मिकों के कल्याण से संबंधित प्रासंगिक मद में व्यय।	2017-18	उत्तराखण्ड राज्य के 05 जनपदों एवं 03 पीएसी वाहिनियों में पुलिस कार्मिकों एवं उनके आश्रितों के इलाज हेतु पुलिस चिकित्सालय अवस्थित हैं। पुलिस कर्मियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। पुलिस कार्मिकों के कल्याणार्थ शासन द्वारा पुलिस विभाग को कल्याण निधि में स्वीकृत अनुदान से पुलिस कार्मिकों के दुर्घटना बीमा का प्रीमियम का भुगतान किया जाना। विकलांग पुलिस कर्मचारियों को एवं उनके आश्रितों को कृत्रिम अंगो हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। खेलकूद निधि से पुलिस विभाग के कुशल खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय स्तर का पदक जीतने पर पुरस्कार प्रदान किया जाना। विभाग के खिलाड़ियों को खेल सामग्री एवं डॉचागत सुविधायें प्रदान किया जाना।	2017-18
18	न्यायालयिक विज्ञान	विधि विज्ञान से सम्बन्धित विभिन्न आपराधों में डी0एन0ए0एवं अन्य परीक्षण कर पुलिस को सहयोग प्रदान करना	-	विधि-विज्ञान प्रयोगशाला में नियुक्त 79 अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन एवं प्रयोगशाला से संबंधित प्रासंगिक व्यय।	2017-18	उत्तराखण्ड राज्य में विधि-विज्ञान प्रयोगशाला में 08 अनुभाग प्रलेख, नारकोटिक्स, भौतिकी, प्राक्षेपिकी, सीरोलोजी, बायोलोजी, डी0एन0ए0, विष एवं रसायन क्रियाशील है तथा निकट भविष्य में कम्प्यूटर फॉरेंसिक एवं वॉयस ऐनेलाइसिस क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित हैं, तथा 02 क्षेत्रीय इकाईयों जनपद देहरादून एवं नैनीताल में स्थापित है। जिसका लाभ अपराध की त्वरित विवेचना में मिल रहा है।	2017-18
19	आन्तरिक सुरक्षा	राज्य की आन्तरिक सुरक्षा में नियुक्त केन्द्रीय पुलिस बलों को भुगतान हेतु धनराशि की व्यवस्था करना।	-	आन्तरिक सुरक्षा हेतु राज्य में नियुक्त सी0पी0एम0एफ0 बल पर प्रासंगिक व्यय।	2017-18	राज्य में आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने हेतु केन्द्रीय पुलिस बल/बाहरी राज्य के पी0ए0सी0 बल की नियुक्ति कर शांति/कानून व्यवस्था बनाये रखना।	2017-18
20	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत अग्निशमन एवं आपात सेवा	अग्निशमन एवं आपात सेवा के आवासीय अनावासीय भवनों का निर्माण	-	अग्निशमन एवं आपात सेवा हेतु प्रशासनिक एवं कार्मिकों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण।	2017-18	पुलिस बल द्वारा निर्विघ्न रूप से कार्य किया जाय इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आवासीय/अनावासीय भवन भी उपलब्ध कराये जाय।	2017-18

21	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना	पुलिस प्रशिक्षण कालेज के निर्माण हेतु आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	-		पी0टी0सी0 के प्रशासनिक/आवासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु।	2017-18	पुलिस बल द्वारा निर्विघ्न रूप से कार्य किया जाय इसके लिए यह आवश्यक है कि उन्हें आवासीय/अनावासीय भवन भी उपलब्ध कराये जाय।	2017-18
22	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (चालू कार्य)	पुलिस विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	-		वर्तमान में प्रचलित अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु।	2017-18	अधूरे निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जायेगा	2017-18
23	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु व्यवस्था (नया कार्य)	पुलिस विभाग के नये आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	-		21 थानों के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु।	2017-18	प्रदेश के नये 21 पुलिस स्टेशनों एवं 85 पुलिस चौकियों के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण से पुलिस बल को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।	2017-18
24	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना	इण्डिया रिजर्व वाहिनी के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण	-		आई0आर0बी0 द्वितीय के प्रशासनिक/आवासीय भवन के निर्माण कार्य हेतु।	2017-18	इण्डिया रिजर्व वाहिनी द्वितीय हेतु राज्य सरकार द्वारा ईस्ट होपटाउन देहरादून में भूमि आवंटित की गयी है। जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना नितान्त आवश्यक है, वर्तमान में इण्डिया रिजर्व वाहिनी के कार्य का संचालन 40 वी वाहिनी पी0ए0सी0 के परिसर से संचालित किया जा रहा है।	2017-18
25	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना	पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज की स्थापना एवं निर्माण	-		पी0टी0सी0 के प्रचलित/अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु।	2017-18	पुलिस प्रशिक्षण कालेज नरेन्द्रनगर के अधूरे कार्य की ई0पी0सी0 हो चुकी है तथा प्रावधानित बजट से अधूरे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करा लिया जायेगा।	2017-18

26	पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स	एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	-		एस0डी0आर0एफ0 की सम्पूर्ण परियोजना की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु।	2017-18	एस0डी0आर0एफ0 के स्वीकृत अनुदान से प्रशासनिक भवन एवं आवासीय भवनों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जिससे एस0डी0आर0एफ0 बल में	2017-18
केन्द्र पोषित योजना								
27	पुलिस बल का आधुनिकीकरण (सी0सी0टी0 एन0एस0)	केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त		-	गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के समस्त पुलिस स्टेशनों और पुलिस के समस्त उच्च कार्यालयों को नेटवर्किंग के द्वारा एक-दूसरे को जोड़े जाने हेतु प्रासंगिक व्यय।	2017-18	यह प्रोजेक्ट गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित मिशन मोड प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश के समस्त पुलिस स्टेशनों और पुलिस के समस्त उच्च कार्यालयों को नेटवर्किंग के द्वारा एक-दूसरे को जोड़ा गया। अपराध तथा अपराधियों की जानकारी का तत्काल आदान-प्रदान किया जाना। योजना से राज्य के सभी 156 पुलिस स्टेशन को जोड़ा गया है। भविष्य में इस योजना के अन्तर्गत न्याय विभाग, अभियोजन, कारागार तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जोड़े जाने प्रस्तावित।	2017-18
28	पुलिस बल का आधुनिकीकरण, पुलिस एवं अन्य बलों के आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय योजना	भारत सरकार द्वारा 80:20 के अन्तर्गत राज्य में पुलिस विभाग की मोबिलिटी बनाये रखने हेतु वाहनों एवं उपकरणों के क्रय हेतु आर्थिक सहायता		-	भारत सरकार द्वारा पुलिस की मोबिलिटी बनाये रखने हेतु वाहनों एवं उपकरणों का क्रय हेतु प्रासंगिक व्यय।	2017-18	भारत सरकार द्वारा पुलिस विभाग की मोबिलिटी बनाये रखने हेतु 90:10 के अनुपात में अनुदान आवंटित किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से पुलिस विभाग के सभी पुलिस थानों हेतु वाहनों एवं उपकरणों का क्रय किया गया। अपराधों पर नियन्त्रण के साथ साथ राज्य में कानून व्यवस्था बनाये रखा जाना।	2017-18
29	केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत पुलिस का आधुनिकीकरण		-		भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण योजना का प्लान अनुमोदन हेतु।	2017-18	भारत सरकार द्वारा आधुनिकीकरण योजना का प्लान अनुमोदन के पश्चात तदनुसार अग्रेंत्तर कार्यवाही प्रचलित की जायेगी।	2017-18